भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1320
उत्तर देने की तारीख : 19.09.2020

पेपरलेस ऑफिस वर्क

†1320. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः
डॉ॰ जयंत कुमार रायः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं (सीईआई) में पेपरलेस ऑफिस वर्क को बढ़ावा देने के लिये कोई नीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) सहित अपने अधीनस्थ एवं स्वायतशासी कार्यालयों में ई- ऑफिस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थी और स्टाफ कार्यालयीन कार्य विभिन्न आवेदन प्रपत्रों, परीक्षाओं इत्यादि जैसे भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिये बड़ी मात्रा में कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों हेतु छुट्टी के आवेदन जैसे विभिन्न मॉडयूल वाले ई-ऑफिस को आरंभ करने की नितान्त आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा कोविड-19 के आलोक में प्रचालन लागत बचाने, कार्बन फूटप्रिन्ट कम करने हेतु केवीएस में पेपरलेस कार्य संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : कोविड- 19 को फैलने से रोकने के लिए पेपरलेस कार्यालयीन कार्य को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा मंत्रालय और स्वायत्त संगठनों जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एनआईसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस नामक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन का उपयोग बढ़ाया गया है। तदनुसार, फाइलों का आदान-प्रदान, छुट्टी आवेदनों आदि पर कार्रवाई ई-ऑफिस के माध्यम से की जाती है। ई-मेल के माध्यम से पत्राचार को बढ़ाया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में, पाठ्यचर्या शिक्षण ऑनलाइन मोड में किया जाता है और डिजिटल डिवाइस के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया गया है। जहां तक संभव हो सकता है, अधिकाधिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती हैं ताकि आमने- सामने बैठना कम से कम हो।

(ग) से (च) : केवीएस सभी संगत फार्म आदि वेबसाइट पर अपलोड करके कागज केइस्तेमाल को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। इसके अलावा सरकारी प्रक्रियाएं जैसे प्रवेश, स्थानांतरण को ऑनलाइन किया गया है। अब मूल्यांकन भी विशेषकर कोविड-19 की परिस्थितियों में ऑनलाइन किया जा रहा है।

*****